point. I want to know whether the Ministry of Industry will be able to help the government of Bihar, would recommend to other counterpart ministries in the Central Government, about the chief constraint in the way of industrial development, namely, finance. How does it relate to any other ministry cannot he help in this?

SHRI CHARANJIT CHANANA: Yes, Sir. We shall definitely support their efforts.

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि उन को कोई ऐसा ज्ञापन नहीं मिला । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दो दिन पहले क्या बिहार के उद्योग मंत्री ने इन के साथ बिहार के औद्योगिक विकास के बारे में विचार-विमर्श किया था या नहीं और बिहार के औद्योगिक विकास में जो कठिनाइयां हैं, उन से इन को अवगत कराया था या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : आनरेबिल मेम्बर ने यह ठीक बताया है कि बिहार के उद्योग मंत्री से हमारी बातचीत हुई है और हम ने उन से रिक्वेस्ट की है कि बिहार के बारे में वे प्लान्स बनवा कर भेजें और जो हैल्प की उन को जरूरत हो, वह हम को बताएं । हम उन की हैल्प जरूर करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम को लगता है कि जब तक किसी चीज के ऊपर मेमोरेण्डम शब्द न लिखा जाए, तब तक मंत्री जी उस को मेमोरेण्डम या ज्ञापन नहीं मानते । बिना मेमोरेण्डम या ज्ञापन लिखे वह मेमोरेण्डम नहीं होता है । मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या बिहार सरकार ने इन के पास 471 करोड़ रुपये की योजना बना कर भेजी है और इस के पहले 425 करोड़ रुपये की योजना बना कर औद्योगिक विकास के लिए इन के पास भेजी थी । मंत्री महोदय कहते हैं कि इनके पास कोई योजना इस तरह की नहीं भेजी गई है । खैर यह मामला तो बाद में निकलेगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन के पास 471 करोड़ रुपये की योजना भेजी गई है या नहीं और बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़े हुए राज्य के विकास की जवाबदेही केन्द्रीय सरकार के ऊपर है । तो छठी योजना में आप उस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री चरणजीत चानना : उद्योग मंत्रालय के पास ऐसी 471 करोड़ रुपये की कोई योजना नहीं आई है । जहां तक छठी योजना का सवाल है, उस के बारे में आप योजना मंत्रालय के पास भेजें । अगर कोई प्रश्न उस के बारे में पूछना है, तो उन के पास आप भेजें ।

Setting up of New Industries in Public Sector in Rajasthan

*868. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Union Government have decided to set up new industries in public sector in Rajasthan during 1980-81;

(b) if so, what are the industries likely to be set up; and

(c) in what areas these will be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले तेरह साल से कोई भी पब्लिक सैक्टर में इण्डस्ट्रीज स्थापित नहीं की गई है ?

क्या यह भी सही है कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान में उद्योग स्थापित होने का अधिक स्कोप होने के बावजूद भी पब्लिक सैक्टर में केवल 1.98 परसेंट की राशि इनवैस्ट की गई है ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: The hon. Member would like to know what are the public sector undertakings which are operating in Rajasthan.

SHRI SATISH AGARWAL: No, that is not his question.

SHRI CHARANJIT CHANANA: The chronology as to when were they set up, for that the information has not been asked and I do not have that information.

The hon. Member, if he wants the date of the installation of the Unit, then I would need notice because in the main question the date of installation has not been asked.

SHRI SATISH AGARWAL: It is a fact that no investment has been made for more than the last ten years?

SHRI CHARANJIT CHANANA: This is not correct. The Rajasthan State has eight public sector projects—Hindustan Copper Limited.... (*Interruptions*).

SHRI SATISH AGARWAL: The question of the hon. Member is—is it a fact that only 2 per cent of investment is there in the public sector in Rajasthan?

SHRI CHARANJIT CHANANA: The question says—whether the Union Government have decided to set up new industries in public sector in Rajasthan during 1980-81? The hon. Member now wants historical data. The historical data has not been asked for in the main question.

MR. SPEAKER: No, there is no question like that. We must have at least his in view—whether we want to set up new industries in public sector in Rajasthan? Whether there are any new undertakings to be taken up?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: The question is composite.

MR. SPEAKER: No, it is not a composite one. You have to put in these....

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: All right, furnish us this information. Thank you.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: क्या यह सही है कि पब्लिक सैक्टर में सवाई माधोपुर, चित्तौड़ और उदयपुर में फर्टिलाइजर प्लांट्स की और कोटा में डिफेंस इण्डस्ट्रीज के खोले जाने का बहुत बड़ा स्कोप है ? क्या उद्योग मंत्रालय इसके संबंध में कुछ सोच रहा है और कोई निर्णय लेने जा रहा है ?

श्री चरणजीत चानना : जिस-जिस इंडस्ट्री का स्कोप है उसके बारे में हमने राजस्थान गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट की है कि वह टैक्नो इकोनोमिक सर्वे कर के बताए । किस-किस इंडस्ट्री का किस-किस इलाके में स्कोप है इसके बारे में हम ने उन से कहा है ताकि जवाब आने पर उस के ऊपर एक्शन लिया जा सके ।

SHRI SATISH AGARWAL: Is it a fact that the Government of Rajasthan has already forwarded proposals with regard to industrialisation of Rajasthan and the Government is considering those proposals and a meeting was held by the former Industries Minister in this connection with the Members of Parliament and decision is yet to be taken by the Government?

The question does not arise with regard to the proposals. The proposals are already there.

SHRI CHARANJIT CHANANA: This question relates to the year 1980-81. The Member is asking question relating his own time.

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के आंगुचा ग्राम में जिंक का बहुत बड़ा भण्डार मिला है ? क्या सरकार सोच रही है कि वहां जिंक स्मेल्टर की स्थापना की जाए ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: We have requested the Government to explore the possibilities.

नये कर्मचारी संघों/महासंघों को मान्यता देने के लिए नियम और विनियम

*869. **श्री दया राम शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों के महासंघों/संघों को मान्यता देने के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या है तथा इसके निर्देश-पद क्या हैं और